THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) to (d) These programmes are uplinked from outside India through foreign satellite. The details of lessees of transponders on foreign satellites are not maintained in this Ministry

Ban on advertisement on Tobacco

2009. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is Government's policy to discourage the use of tobacco by the people in any form;

(b) if so, what are the reasons for permitting advertisements in bold lines and colours about cigarette smoking in newspapers and magazines and on hoardings in the streets; and

(c) the steps proposed to discourage or ban such advertisements?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The information is being collected.

देश में पन विद्युत परियोजनाओं का अंशदान

2010. **श्री राम जेठमलानी**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विगत चार दशकों के दौरान देश के विद्युत उत्पादन क्षेत्र में पन विद्युत उत्पादन का अंशदान निरंतर घटता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पचास और नब्बे के दशक के दौरान पन विद्युत उत्पादन का अंशदान कितना-कितना था और क्या यह भी सच है कि पन विद्युत के क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की पर्याप्त संभावना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस क्षेत्र में विद्युत के उत्पादन हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र को आकर्षित करने के वास्ते अनेक सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) जुलाई, 1993 तक सरकार को पन विद्युत क्षेत्र में विद्युत के उत्पादन हेतु कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू): (क) और (ख) पचास के दशक में जल विद्युत तथा ताप विद्युत (न्यूक्लीय सहित) अधिष्ठापित क्षमताओं का अनुपात 32.6% से 34.8% के बीच रहा और वर्ष 1990-91 तथा 1992-93 के दौरान देश के समग्र विद्युत उत्पादन क्षमता में जल विद्युत का योगदान 20.4% से 27.05% के बीच रहा था। देश में 84000 मेगावाट जल विद्युत शक्यता होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) से (ङ) अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने की दृष्टि से सरकार ने विद्युत के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु एक नीति की घोषणा की है और उसको क्रियान्वित कर रही है। अभी तक निजी क्षेत्र ने 10 जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किए जाने के प्रति रूचि दिखाई है। विशेष परियोजनाओं के बारे में परियोजना घटकों के साथ नियमित रूप से विचार विमर्श किए जा रहे हैं। तथा इस नीति की गहन रूप से समीक्षा की जा रही है। निजी क्षेत्र द्वारा क्षमता अभिवृद्धि किये जाने के परिणामस्वरूप देश में कुल मिलाकर विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार होगा।